राज्यसभा चुनाव • 18 जून को चुनाव, रणनीतिक तैयारियों में जुटी भाजपा और कांग्रेस पार्टियां

दिल्ली में हेमंत और मोहन ने राष्ट्रीय नेतृत्व से किया मंथन, एक-दो दिन के अंदर प्रत्याशियों की घोषणा

पॉलिटिकल रिपोर्टर / भोपाल

प्रदेश में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा की रणनीतिक तैयारियां पूरी हो गई हैं, राज्यसभा प्रत्याशियों के नामों को लेकर मुख्यमंत्री दिल्ली से लेकर भोपाल तक राजनीतिक हलचल तेज। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दिल्ली दौरे और प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की दिल्ली से भोपाल वापसी के बाद माना जा रहा है कि पार्टी आलाकमान ने संभावित नामों पर प्रदेश नेतृत्व से अंतिम चर्चा कर लिलेकिन नामों की घोषणाएं दे दी है। अगले एक-दो दिन में इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। भाजपा सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा चुनावों के जरिए पार्टी अगली संगठनात्मक प्रक्रियाओं को साधने जा रही है। मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष के दिल्ली दौरों के बाद अब मेरे पूरी तरह केंद्रीय चुनाव समिति (सीईसी) के पाले में है। माना जा रहा है कि अगले 48 घंटों में दिल्ली से हरी झंडी मिलते ही पार्टी अपने अधिकृत नामों का ऐलान कर देगी।

दो दिन से खंडेलवाल का दिल्ली में डेरा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भाजपा को दिल्ली में केंद्रीय उच्च पर्यवेक्षक नरेंद्र मोदी पीयूष गोयल अनिल कर्वे पार्टी पदाधिकारियों और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। अधिकांश तौर पर यह मुलाकात विभिन्न नामों को लेकर थी, लेकिन माना जा रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने राज्यसभा चुनाव की रणनीति और प्रदेश संगठन के हलचुट पर सीधा से चर्चा की है। इससे तीन पहले, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दो दिनों तक दिल्ली में डेरा डाले हुए थे। वहां केंद्रीय नेतृत्व के साथ वर्ष महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठकों में शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक, इन बैठकों में राज्यसभा संगठन की ओर से तैयार नामों पर चर्चा, केंद्रीय संतुलन और सामाजिक समीकरणों पर पूरा खाका केंद्रीय आलाकमान के सामने रखा गया। राष्ट्रीय नेतृत्व से आज दिन-दिहाड़े होने के बाद प्रदेशाध्यक्ष मुख्यमंत्री को वापस भोपाल लौट आए हैं।

मध्यप्रदेश कांग्रेस में दावों की होड़, 5 जून को होगा दिल्ली में होगा फैसला

राज्यसभा की एक सीट के लिए कांग्रेस खेमे में दावेदारों की फेहरिस्त लंबी होती जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी और सीडब्ल्यूसी मेंबर कालीचरण पटेल के नामों की चर्चा पकड़ में है, लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाम चर्चा में आ गया है।

इस बीच, उम्मीदवारों के चयन को लेकर 5 जून को दिल्ली में एक बड़ी और निर्णायक बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एम के विपक्ष नेताओं के साथ मंथन करेंगे। बैठक में शामिल होने के लिए मप्र कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के अनुसार, पिछड़ा नामों की कई अंतिम सूचियां तैयार नहीं हुई हैं।

पीडब्ल्यूडी • जांच रिपोर्ट में कुल 11 इंजीनियरों को बताया गया था दोषी

गारंटी वाली सड़कों पर व्हाइट टॉपिंग मामले में 9 इंजीनियरों को नोटिस... 2 के नाम हटाए

विशेष संवाददाता / भोपाल

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा पर्यवेक्षित गारंटी (पीजी) अवधि वाली सड़कों पर टेस्टेड व्हाइट टॉपिंग के प्रस्ताव भेजने के मामले में नई कार्रवाई अब सामने के मोड़ में है। विभाग ने इस मामले में 9 एक्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। लेकिन, मुख्य अभियंता कार्यालय द्वारा तैयार की गई मूल जांच रिपोर्ट सामने आई। तब पता चला कि इस महामारी में शामिल कुछ अन्य इंजीनियरों को नोटिस नहीं जारी किए गए। इनमें विनय सिंह (तत्कालीन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, भोपाल संभाग-2) और अनंत सिंह रघुवंशी (तत्कालीन एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, भोपाल संभाग) का नाम शामिल है। चीफ इंजीनियर (भोपाल परिमंडल) संभग मनके द्वारा प्रमुख अभियंता को भेजी गई 11 मिसलिंक नामों की समीक्षा रिपोर्ट में कुल 11 इंजीनियरों को दोषी के रूप में चिह्नित किया गया था। उनमें इन दोनों के नाम शामिल थे।

किसके पास कौन सी सड़क थी

विजय सिंह : डीआईजी गंगले से काली पीठ होते हुए मेट्रो ब्रांच (अयोध्या बायपास नगर) तक 14.48 करोड़ रुपए की लागत वाले व्हाइट टॉपिंग कार्य का प्रस्तावन भेजने के लिए इन्हें जिम्मेदार पाया गया था। इस नामों का एक विस्तृत पत्रावलियां गहरी में था।

न्यू भोपाल और डिवीजन-2 की कई सड़कें भी शामिल

नया भोपाल संभाग और रायपुरी संभाग क्रमांक-2 के अंतर्गत ऐसी कई अन्य सड़कें थीं। इन्हें गारंटी अवधि में होने के बावजूद व्हाइट टॉपिंग में शामिल किया गया था। इन सड़कों में न्यू भोपाल संभाग की 07 नंबर मस्त स्टोर से मनीष मार्केट मार्ग (लगत 8.56 करोड़) और हनुमान मार्केट से राष्ट्रीय रायपुरी-12 मार्ग (लगत 2.08 करोड़ रुपए) शामिल हैं। अलेप बोर्डों में के अंतर्गत ऐसी कई सड़कें भी शामिल थी। इनकी लागत 13.48 करोड़ रुपए थी। यहीं भोपाल क्रमांक-2 के अंतर्गत भदा नगर कैनाल रोड (लगत 6.55 करोड़ रुपए) और भोपाल डाट जंक्शन से ब्यावरा चौराहा मार्ग (पीजी सम्पदित लागत 13 मई 2025) को निम्नांकित के निकट प्रस्तावित किया गया था।

मुरैना की खड़गपुर पंचायत में खुलासा... एफआईआर के दिए निर्देश

वीबी रामजी लागू होने से पहले ही फर्जीवाड़ा, एप का क्लोन तैयार कर दर्ज कराई हाजिरी

पॉलिटिकल रिपोर्टर / भोपाल

मनरेगा का नाम बदलकर वीबी रामजी योजना का किया गया है, जो 1 जुलाई से प्रदेशभर में लागू होगी। योजना में पारदर्शिता के लिए ऐप्स ऑपरेटिंग और एनएमएमएस ऐप आधारित उपस्थिति व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत मजदूरों की हाजिरी कार्यस्थल पर पहुंचने के बाद चेहरे के सत्यापन से दर्ज की जानी है। लेकिन नवलपुर के इस मामले ने पहले ही एप का बनाने तैयार कर फर्जी हाजिरी लगाने का फायदा उठाने आरंभ है। मुरैना जिले की खड़गपुर ग्राम पंचायत में जांच के दौरान पता चला कि यहां ऐसे मजदूरों की भी उपस्थिति दर्ज की गई, जो कभी काम पर नहीं गए। हालत ही नहीं, एक मजदूर के नाम पर बताया-अलग दिनों में यहां लोगों की हाजिरी अलग-अलग की गई। कलेक्टर ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। इसकी जानकारी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भेज दी है।

पहले से खींची गई फोटो दर्ज करने का विकल्प नहीं

- जियो-टैगिंग – काम पर किसी कार्यस्थल पर मजदूरों की उपस्थिति ली जाती है, तो एप मोबाइल के कैमरे का उपयोग करके उस स्थल को लिंकेट करता है। इससे पुनरिपयोग होता है कि उपस्थिति वास्तविक कार्यस्थल से ही ली जा रही है।
- फेस ऑथेंटिकेशन और लाइव फोटो – एप के माध्यम से कार्यस्थल पर मौजूद मजदूरों की लाइव फोटो लेकर उनकी हाजिरी दर्ज की है। सुरक्षा मानकों के अनुसार, इसमें पहले से खींची गई या गैलरी से चुनी गई फोटो अस्वीकार करने का विकल्प नहीं होता।

और वीबी जिलों में इस तरह के मामलों की आशंकाएं जांच में यह बात सामने आई है कि यह मामला सिर्फ मुरैना तक सीमित नहीं है। राज्यभर अन्यजिलों में इस नवलपुरी प्रॉपरटेक्स की पहचान और लिंक को अंतिमरूप बेचना शुरू कर दिया है। प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी इसी प्रकार की फर्जी हाजिरी लगाई जा रही थी।

ऐसे सामने आया फर्जीवाड़ा: असली एप में निगम है कि मजदूर को काम की जगह पर खड़े होकर ही अपनी उपस्थिति चिह्नांकनी होगी। लेकिन इस नवलपुरी एप के जरिए कोई भी मजदूर घर बैठे भी मोबाइल, किसी भी पुरानी फोटो अपलोड करके फर्जी हाजिरी लगा सकता है। अब प्रदेश के सभी जिलों में इस एप के जरिए हुई हाजिरी की जांच कराई जा रही है।

पेट्रोल कार छोड़ी... सीएम अब इलेक्ट्रिक कार से करेंगे सफर

मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक ईवी से पहुंचे

भोपाल / भोपाल में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हैन चयत और पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्य नई पहल की। उन्होंने मुख्यमंत्री निवास से स्टेट हैंगर तक पेट्रोल वाहन की बजाय इलेक्ट्रिक वाहन से यात्रा की।

सुरक्षा कारणों, शौचयों की जांच और जरूरी प्रोटोकॉल पूरी होने के बाद यह ईवी लघु कलेक्ट में शामिल की गई है। अब राजधानी में ये निर्माण रूप से ईवी कार से ही आवागमन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों से हैन की अधिकतम चयत और पितामातृपूर्ण यात्रा के साधन अपनाने का संदेश दिया है। उन्होंने बताया कि सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। ईवी से चलने वाले वाहन नहीं होता, शोर कम रहता है और संचालन लागत पारम्परिक ईंधन चाले वाहनों की तुलना में कम होती है।

विद्युत पेंशनर्स की संयुक्त बैठक में 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले सदस्यों का सम्मान

भोपाल | विद्युत पेंशनर्स हित रक्षक संघ मिल भोपाल और प्रदेश कार्यकारिणी की संयुक्त महिला बैठक बाल मंदिर परिसर, प्लाइवेट मिलनी कॉलोनी, गोविंदपुरा में हुई। शुभारात्र शुरुआत से हुई। एजेंडे के अनुसार नई यह में जन्मदिन वाले सदस्यों का श्रीफल और पुष्पगुच्छों से सम्मान हुआ। 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ पेंशनर्स का शाल, श्रीफल और पुष्पगुच्छों से सम्मान हुआ।

भारतीय स्टेट बैंक
मुख्य शाखा, इटारसी (म.प्र.)
कोड: 07572-236157
संशोधन
दिनांक 22.04.2026 को इस शाखा द्वारा "अपना संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी" प्रकाशित किया गया था। जिसमें श्री शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल की सम्पत्ति की ई-नीलामी दिनांक 02.06.26 निर्धारित की गई थी जो तकनीकी कारणवश के कारण आयोजित नहीं हो सकी। अब यह ई-नीलामी दिनांक 15.06.2026 एवं सम्पत्ति निरीक्षण दिनांक 10 से 10जून 2026 को प्रस्तावित है। शेष यथावत रहेगा।
प्राधिकृत अधिकारी

आम सूचना
जिन पेंशन धारकों ने 31 दिसंबर 2025 तक जीवित होने का प्रमाण नहीं दिया है, उन्हें 30 जून तक जमा करना है।
श्री अनंत कुमार अग्रवाल की अधिकृत मालिकी इन्हें के अधिकृत मालिकी इन्हें के अधिकृत मालिकी इन्हें के